(ii) development and strengthening of adaptive research facilities through the provision of additional staff, vehicles, simple farm equipments and buildings; and

(iii) monitoring the progress of the Project and evaluating its impact through the provision of staff, equipment, vehicles and funds.

(c) The assistance would be channelised through the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, which is the nodal agency for all aid from the World Bank The programme would be carried out in all the 31 administrative districts of Bihar.

(d) Yes, Sir, the IDA has already approved the following credits for similar projects in the States of West Bengal, Orissa and Assam:

West Bengal	12 million dollars
Orissa	20 million dollars
Assam	8 million dollars

गुजरात में खाद्यान्नों का उत्पादन

1702. **श्री अमरसिंह बी० सठवा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि गुजरात के उन क्षेत्रों, विशेष कर आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई है —सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मक्का तथा ज्वार खाने वाले आदिवासी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए कोई प्रबन्ध किया है; अथवा गुजरात राज्य को तत्सम्बन्धी अनुदेश दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गुजरात सरकार ने सिर्फ यह सूचित किया था कि भारी और असामयिक वर्षा के कारण राज्य के मोटे अनाजों की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के आन्तरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । गुजरात सरकार की गेहूं और चावल की मांगों को पूरी तरह से पूरा किया जाता है । गुजरात सरकार को यह सूचित किया गया है कि राज्य में वितरण के लिए राज्य सरकार को गेहूं की जितनी भी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होगी केन्द्रीय सरकार उसका आवंटन करने की स्थिति में है । केन्द्रीय पूल में आयातित माइलो का स्टाक लगभग समाप्त हो गया है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य मोटे अनाजों की आन्तरिक वसूली केवल समर्थन मूल्य के रूप में की जाती है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वस्तुत अब तक कोई वसूली नहीं की गई है । इसके फलस्वरूप, गुजरात सरकार की माइलो अथवा अन्य मोटे अनाजों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका । तथापि, गुजरात सरकार को यह सूचित किया गया है कि यदि राज्य सरकार माइलो अथवा अन्य मोटे अनाजों के स्थान पर गेहूं लेना चाहे तो उन्हें गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है । राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइलो की कुछ मात्रा आयात करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।